समक्ष ऋतु बाहरी, माननीय न्यायमूर्ति।

परवीन *कुमार* – *अपीलकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य – प्रतिवादी

आपराधिक अपील संख्या 2004 का एस -665-एसबी

13 जनवरी 2015

***भारतीय दंड संहिता, 1860* - धारा *363, 366A और 376* - दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* - धारा *161, 164, 313* - नाबालिग का अपहरण और बलात्कार- यह पाते हुए कि पीड़िता नाबालिग थी, सहमति की दलील टिक नहीं पाती है - दोषसिद्धि की पुष्टि हुई।**

अभिनिर्णित, हेडमास्टर ने P.W.3 के रूप में पेश होते हुए कहा था कि पीड़िता 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसने 10.07.2001 को होली हार्ट हाई स्कूल, हिसार में 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया था और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी जन्म तिथि 08.01 है। 1989. उसका बड़ा भाई भी उसी कक्षा में पढ़ता था। उन्होंने आगे कहा कि प्रवेश पत्र भरा गया था और अभिभावक के रूप में सरिता (अभियोक्ता की बड़ी बहन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया था। अभियोक्त्री के पिता राम किशन का शपथ पत्र भी प्रवेश पत्र के साथ संलग्न था। बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य का खंडन करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे खंडित नहीं किया गया है। कथित घटना के समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी और इस प्रकार, वह उस रिश्ते में सहमति देने वाली पक्ष नहीं हो सकती थी जहां अपीलकर्ता द्वारा उसका शोषण किया गया था। अपीलकर्ता, जो पीड़िता के करीबी पारिवारिक रिश्ते में था, रिकॉर्ड पर जन्मतिथि प्रमाण पत्र या नगरपालिका परिषद या अस्पताल से कोई अन्य सबूत रखकर यह दिखा सकता था कि कथित घटना के समय वह बालिग थी। इसलिए, एक्स पीबी को अधिक से अधिक द्वितीयक साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है।

(पैरा 13)

आगे कहा गया, स्कूल के हेडमास्टर ने एक्स पीबी यानी स्कूल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को साबित कर दिया था और पीड़िता की उम्र की जांच ट्रायल कोर्ट द्वारा डॉ. अनीता बंसल, पी.डब्ल्यू.6 के बयान के आधार पर की गई थी, जहां पीड़िता की उम्र थी 14 वर्ष बताया गया।

(पैरा 14)

इसके अलावा, यह माना गया कि अपीलकर्ता, परिवार का करीबी रिश्तेदार होने के नाते, पीड़िता का यह बयान कि उसके साथ 25.06.2002 से पहले भी बलात्कार किया जा रहा था, खारिज करने योग्य नहीं है क्योंकि जिरह में डॉ. बंसल ने कहा कि पीड़िता संभोग का आदी. अभियोजन पक्ष ने इस प्रकार साबित कर दिया कि अपीलकर्ता नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। अत: अपील खारिज किये जाने योग्य है।

(पैरा 22)

आगे कहा कि नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म का अपराध गंभीर अपराध है। परिवार की इज्जत दांव पर लग गयी. यौन हिंसा अमानवीय कृत्य होने के अलावा महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार पर एक गैरकानूनी घुसपैठ है। यह उसके सर्वोच्च सम्मान के लिए एक गंभीर आघात है और उसके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाता है। यह पीड़ित को अपमानित और अपमानित करता है और निर्दोष नाबालिग लड़की के मामले में, यह एक दर्दनाक अनुभव छोड़ जाता है। बलात्कार केवल एक महिला के प्रति अपराध नहीं है, यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है।

(पैरा 23)

आगे कहा गया, कि इस प्रकार, समाज में अस्वीकृति की भावना के साथ जीने के लिए कम आत्मसम्मान के अलावा, पीड़ित ने अपने पिता का भावनात्मक समर्थन भी खो दिया, जिनकी शिकायत 28.06.2002 को दर्ज होने के एक सप्ताह के भीतर यानी 02.07.2002 को मृत्यु हो गई।

(पैरा 25)

आगे कहा गया कि वर्तमान अपील गुण-दोष के आधार पर खारिज की जाती है। हालाँकि, उपरोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए, यह न्यायालय राज्य को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देता है और पीड़िता को अतिरिक्त 5 लाख रुपये भी दिए जाते हैं क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। 28.06.2002 को शिकायत दर्ज होने के बाद 02.07.2002 को।

(पैरा 27)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन.सी. किनरा।
सी.एस. बख्शी, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा।

ऋतु बाहरी, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) अपीलकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा पारित सजा के फैसले दिनांक 11.03.2004 और सजा के आदेश दिनांक 12.03.2004 के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत उसे धारा 363/366 के तहत सात साल की अवधि के लिए पर्याप्त रूप से दोषी ठहराया गया है। पुलिस स्टेशन सिटी हिसार में दर्ज एफआईआर नंबर 324 दिनांक 28.06.2002 में भारतीय दंड संहिता का ए/376 (संक्षेप में "कोड")।

(2) अभियोजन पक्ष के अनुसार बी.डी.ओ. में चपरासी के पद पर कार्यरत शिकायतकर्ता राम किशन ने 28.06.2002 को एक शिकायत दर्ज कराई थी। कार्यालय, बरवाला ने पुलिस को बताया कि उसकी तीन बेटियां और एक बेटा है जिनके नाम संगीता, सरिता, सतीश और किरण हैं। सबसे बड़ी संगीता और सरिता की शादी हो चुकी है। अभियोक्ता किरण की उम्र 14/15 वर्ष है और उसने 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा दी थी। आरोपी-परवीन कृष्ण (जो शिकायतकर्ता का जीजा है) का जीजा है। परवीन कृष्ण के साथ रह रही है और शिकायतकर्ता के साथ उसका आना-जाना था और वह अक्सर उसके घर आती रहती थी। दिनांक 25.06.2002 को, शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी अपने घर पर नहीं थे और जब शिकायतकर्ता संतोष की पत्नी घर लौटी, तो उसने किरण को गायब पाया और शिकायतकर्ता को यह घटना बताई। फरियादी ने किरण को अपनी रिश्तेदारी में तलाश किया। शिकायतकर्ता को संदेह था कि उसकी बेटी किरण को प्रवीण बहला-फुसलाकर ले गया है, इसलिए उपरोक्त एफ.आई.आर. उनके द्वारा पंजीयन कराया गया था। इसके बाद, अभियोजक किरण को 30.06.2002 को बस स्टैंड, हिसार से आरोपी-परवीन की हिरासत से बरामद किया गया। उन दोनों की सी.एच., हिसार में चिकित्सीय जांच की गई। डॉक्टर ने पीड़िता का स्वाब, सलवार और अंडरवियर भी अपने कब्जे में ले लिया और पुलंदा में तब्दील करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। आरोपी का अंडरवियर भी कब्जे में ले लिया गया। पीड़िता के स्वाब और कपड़ों के साथ-साथ आरोपी के अंडरवियर को विश्लेषण के लिए एफएसएल भेजा गया था। रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अभियोक्ता के स्वाब और कपड़ों तथा आरोपी के अंडरवियर पर मानव वीर्य पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा एक रफ साइट प्लान तैयार किया गया था और यह साबित करने के लिए कि अपराध के समय वह नाबालिग थी, पीड़िता का स्कूल प्रमाण पत्र भी एकत्र किया गया था। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान 23.07.2002 को इलाक़ा मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा 376 भी जोड़ी गई।

(3) उसके खिलाफ 07.09.2002 को संहिता की धारा 363/366-ए/376 के तहत आरोप तय किए गए थे, जिस पर आरोपी ने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमे का दावा किया।

(4) मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में, अपीलकर्ता ने अभियोजन के आरोपों से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया। बचाव में, उन्होंने मौखिक साक्ष्य के रूप में DW1 बबली की जांच की।

(6) जैसा कि ऊपर बताया गया है, ट्रायल कोर्ट ने पूरे सबूतों को देखने के बाद अपीलकर्ता को दोषी ठहराया।

(7) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री किनरा ने तर्क दिया कि अभियोजक किरण की जन्मतिथि के संबंध में एकमात्र साक्ष्य होली हार्ट हाई स्कूल, हिसार द्वारा जारी एक्स पीबी था, जिसके लिए उसने 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया था और केवल यह एक्सपीबी अभियोक्ता की उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसे 10.07.2001 को स्कूल में दाखिला मिला था, लेकिन जिस स्कूल से उसने पहले स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, उसका रिकॉर्ड अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र और प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह निजी स्कूल था और इस प्रमाणपत्र के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसकी जन्मतिथि 08.01.1989 है।

(8) उनके तर्क को बल देने के लिए, सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य1 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है। आगे **अरविंदर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य** के मामले में इस न्यायालय के फैसले **और रमेश शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य** के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है।

(9) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि आरोपी शिकायतकर्ता के परिवार का करीबी रिश्तेदार था और पी.डब्लू.6 के बयान के अनुसार, उसने कहा कि पूरे शरीर पर चोट का कोई बाहरी निशान नहीं देखा गया था। बाहरी जननांग या जांघ पर कोई चोट नहीं पाई गई। कोई रक्तस्राव मौजूद नहीं पाया गया। हाइमन अनुपस्थित थी. जिरह में उसने कहा कि अभियोक्ता को संभोग करने की आदत थी। इस प्रकार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया है। इसलिए, यह पीड़िता की सहमति का मामला था और अपीलकर्ता के खिलाफ संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप नहीं लगाया गया है।

(10) विद्वान वकील के इस तर्क से निपटने के लिए कि अपराध करने के समय पीड़िता बालिग थी, पी.डब्ल्यू. के बयान का संदर्भ लिया जा सकता है। 3 धर्म चंद दलाल, स्कूल के हेड मास्टर, जो अभियोक्ता किरण का प्रवेश रिकॉर्ड लेकर आए थे और कहा था कि राम किशन की बेटी ने 10.07.2001 को उनके स्कूल में 8वीं कक्षा

में प्रवेश लिया था और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी तारीख जन्म तिथि 08.01.1989 है. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र भरा गया था और अभिभावक के रूप में सरिता (अभियोक्ता की बड़ी बहन) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। प्रवेश पत्र के साथ पीड़िता के पिता राम किशन का शपथ पत्र भी संलग्न था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि राम किशन के शपथ पत्र के अलावा नगर परिषद या अस्पताल का कोई अन्य प्रमाण फॉर्म के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसके अलावा राम किशन (अभियोक्ता के पिता की मृत्यु 02.07.2002 को हो गई और वह ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके।

(11) **सतपाल सिंह के मामले (सुप्रा)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मामले से निपटते हुए पैराग्राफ 27 और 28 को निम्नानुसार रखा:-

"27. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि किसी अधिकारी या आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन में अधिकृत व्यक्ति द्वारा आधिकारिक रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्य है, लेकिन पार्टी अभी भी न्यायालय/प्राधिकरण से पूछ सकती है। इसके संभावित मूल्य की जांच करें। प्रविष्टि की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि ऐसी प्रविष्टि किसके निर्देश/सूचना पर दर्ज की गई थी और उसकी जानकारी का स्रोत क्या था। इस प्रकार, स्कूल रजिस्टर/प्रमाणपत्र में प्रविष्टि को कानून के अनुसार साबित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सबूत का मानक किसी भी अन्य नागरिक और आपराधिक मामले की तरह ही रहता है।

28. यदि उपरोक्त निर्धारित कानूनी प्रस्ताव के आलोक में मामले की जांच की जाती है, तो स्कूल रजिस्टर में दर्ज पीड़िता की जन्मतिथि की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। यह पता लगाना संभव नहीं है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने प्राथमिक विद्यालय में प्रारंभिक प्रवेश के समय उसकी जन्मतिथि 13.02.1975 बताई थी। मोरेसो, यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने प्राथमिक विद्यालय रजिस्टर में उसकी जन्मतिथि दर्ज की थी। मोरेसो, प्राथमिक विद्यालय रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में प्रविष्टि ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत और साबित नहीं की गई है। इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि अभियोक्ता बालिग थी। जो भी हो, यदि अभियोजन सफलतापूर्वक यह स्थापित कर दे कि यह सहमति का मामला नहीं था, तो बहुमत का मुद्दा अप्रासंगिक हो जाता है।"

(12) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलकर्ता की सजा का समर्थन किया है और कहा है कि अपीलकर्ता को दी गई सजा में हस्तक्षेप होने की संभावना नहीं है और इस प्रकार, अपील खारिज की जा सकती है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने

अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। संदेह की सभी छायाओं से परे।

(13) वर्तमान मामले में, हेडमास्टर ने P.W.3 के रूप में पेश होते हुए कहा था कि पीड़िता 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसने 10.07.2001 को होली हार्ट हाई स्कूल, हिसार में 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया था और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी तारीख जन्म 08.01.1989 है. उसका बड़ा भाई भी उसी कक्षा में पढ़ता था। उन्होंने आगे कहा कि प्रवेश पत्र भरा गया था और अभिभावक के रूप में सरिता (अभियोक्ता की बड़ी बहन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया था। प्रवेश पत्र के साथ पीड़िता के पिता राम किशन का शपथ पत्र भी संलग्न था। बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य का खंडन करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे खंडित नहीं किया गया है। कथित घटना के समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी और इस प्रकार, वह उस रिश्ते में सहमति देने वाली पक्ष नहीं हो सकती थी जहां अपीलकर्ता द्वारा उसका शोषण किया गया था। अपीलकर्ता, जो पीड़िता के करीबी पारिवारिक रिश्ते में था, रिकॉर्ड पर जन्मतिथि प्रमाण पत्र या नगरपालिका परिषद या अस्पताल से कोई अन्य सबूत रखकर यह दिखा सकता था कि कथित घटना के समय वह बालिग थी। इसलिए, एक्स पीबी को अधिक से अधिक द्वितीयक साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है।

(14) इसके अलावा अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री किनरा ने उद्धृत किया है इस न्यायालय के फैसले यानी अरविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, से अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि धारा 376 आईपीसी के तहत उस मामले में, जिस व्यक्ति ने पीड़िता को भर्ती कराया था, उसकी जांच नहीं की गई थी और सर्वोत्तम साक्ष्य के अभाव में प्रवेश रजिस्टर के प्रपत्र में, अभियोजक की आयु 18 वर्ष और सहमति देने वाला पक्ष माना गया। वर्तमान मामले में, स्कूल के प्रधानाध्यापक ने एक्स पीबी यानी स्कूल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को साबित कर दिया था और पीड़िता की उम्र की जांच ट्रायल कोर्ट द्वारा डॉ. अनीता बंसल, पी.डब्लू.6 के बयान के आधार पर की गई थी, जहां पीड़िता की उम्र बताई गई थी। पीड़िता की उम्र 14 साल बताई गई है।

(15) इसके अलावा, वर्तमान मामले में, पीड़िता के पिता राम किशन द्वारा एक शिकायत पूर्व पीके दर्ज कराई गई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किरण की उम्र 14/15 वर्ष है और जून, 2002 में वह 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल हो चुकी है। कक्षा। इस शिकायत के बाद कोई तथ्य छुपाया नहीं गया, किरण को 30.06.2002 को आरोपी परवीन की हिरासत से बरामद किया गया और सी.एच. में उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। किरण ने अपनी मेडिकल जांच के समय अपनी उम्र 14 वर्ष बताई थी, जिसका उल्लेख आगे पी.डब्ल्यू.6 डॉ. अनिता बंसल ने एमएलआर एक्स पीएफ में किया है।

(16) पी.डब्लू.9- किरण और पी.डब्लू.10 संतोष देवी ने कहा था कि दोनों बड़ी बहनों संगीता और सरिता की शादी हो चुकी है और वे किरण से बड़ी हैं। P.W.9 और P.W.10 के बयानों से राम किसन और संतोष की शादी का अनुमानित वर्ष और उनके बच्चों में अंतर भी पता चलता है कि अभियोक्ता की उम्र लगभग 14 वर्ष है। बचाव पक्ष पी.डब्ल्यू के बयानों की सत्यता को चुनौती देने में विफल रहा है। 9 और पी.डब्ल्यू.10 किरण की उम्र के संबंध में इस तथ्य के बावजूद कि उनसे विस्तार से जिरह की गई थी।

(17) इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क खारिज कर दिया जाता है कि 28.06.2002 को अभियोजक की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी।

(18) पी.डब्लू.1, 2, 4 और 8 आधिकारिक गवाह थे और उन्होंने अभियोजन संस्करण का विधिवत समर्थन किया है। पी.डब्ल्यू.12 जगदीश चंदर, एस.आई. के बयान के अनुसार, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत किरण का बयान दर्ज किया था और पीड़िता और आरोपी दोनों को सिविल अस्पताल, हिसार ले आए थे।

(19) अधिक से अधिक, अभियोजन पक्ष की ओर से यह चूक हुई कि उन्होंने पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में प्रारंभिक साक्ष्य एकत्र नहीं किए थे। यह चूक स्वयं अभियोजन के मामले में कोई बाधा नहीं डाल सकती।

(20) अपीलकर्ता ने पीड़िता के करीबी पारिवारिक रिश्ते में होने के कारण उसका तब शोषण किया जब उसके माता-पिता घर पर नहीं थे। अभियोजन पक्ष 25.06.2002 को अपीलकर्ता के साथ मुल्लांपुर गांव गया था और उसके बाद वे मूर्ति देवी के घर गए। इसके बाद वे बस से लाडोट गांव गए जहां वे आरोपी के चाचा के परिवार के साथ 29.06.2002 तक रहे। वे 30.06.2002 को वापस हिसार आये और अंततः पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये। P.W.9 ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने 25.06.2002 से पहले भी उसके साथ बलात्कार किया था। उसने स्वीकार किया था कि उसने 25.06.2002 से पहले आरोपी द्वारा बलात्कार किए जाने के बारे में अपने माता-पिता को नहीं बताया था।

(21) वर्तमान मामले में, बबली (कृष्ण की पत्नी) के बयान के अनुसार, कृष्ण (शिकायतकर्ता के बहनोई) ने परवीन को किरण से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन वह सहमत नहीं थी और राम किशन ने उसे इस मामले में झूठा फंसा दिया था। . घटना के 4-5 दिन बाद रामकिशन उसके पास आया और दुखी होकर उसने यह भी कहा कि वह आत्महत्या कर लेगा. अगले दिन राम किशन ने वाटर वर्क टैंक, हिसार में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के दो महीने बाद किरण भी अपने घर आई और खुलासा किया कि उसके माता-पिता के दबाव के कारण आरोपी के खिलाफ झूठा मामला बनाया गया था। अभियोक्त्री किरण को दिनांक 30.06.2002 को बस स्टैंड, हिसार से आरोपी परवीन की हिरासत से बरामद किया गया था। उन दोनों का सी.एच., हिसार

में चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और मेडिकल परीक्षण के समय किरण ने अपनी उम्र 14 वर्ष बताई, जिसका उल्लेख आगे पी.डब्ल्यू.6 डॉ. अनिता बंसल ने एमएलआर एक्स पीएफ में किया। डॉ. अनीता बंसल ने कहा कि उन्होंने 28.06.2002 को बलात्कार के कथित इतिहास वाली 14 साल की किरण की चिकित्सकीय जांच की थी। जिरह में उसने कहा कि अभियोक्ता को संभोग करने की आदत थी। पी.डब्लू.9- किरण और पी.डब्लू.10 संतोष देवी के बयान के अनुसार, पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी, जैसा कि प्रवेश पत्र से स्पष्ट था, क्योंकि उसे 10.07.2001 को 8वीं कक्षा में स्कूल में प्रवेश दिया गया था, जिसे भरा गया था। और अभिभावक के रूप में सरिता (अभियोक्ता की बड़ी बहन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित। उनकी जन्मतिथि 08.01.1989 दर्ज की गई थी। 25.06.2002 को अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता को मुल्लांपुर गांव ले जाया गया और उसके बाद वे मूर्ति देवी के घर गए। इसके बाद वे बस से लाडोट गांव गए जहां वे आरोपी के चाचा के परिवार के साथ 29.06.2002 तक रहे। वे 30.06.2002 को वापस हिसार आये और अंततः पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

(22) अपीलकर्ता, परिवार का करीबी रिश्तेदार होने के नाते, पीड़िता का बयान कि उसके साथ 25.06.2002 से पहले भी बलात्कार किया जा रहा था, खारिज करने योग्य नहीं है क्योंकि जिरह में डॉ. बंसल ने कहा कि पीड़िता संभोग करने की आदी थी। . अभियोजन पक्ष ने इस प्रकार साबित कर दिया कि अपीलकर्ता नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। अत: अपील खारिज किये जाने योग्य है।

(23) नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार का अपराध गंभीर अपराध है। परिवार की इज्जत दांव पर लग गयी. यौन हिंसा अमानवीय कृत्य होने के अलावा महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार पर एक गैरकानूनी घुसपैठ है। यह उसके सर्वोच्च सम्मान के लिए एक गंभीर आघात है और उसके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाता है। यह पीड़ित को अपमानित और अपमानित करता है और निर्दोष नाबालिग लड़की के मामले में, यह एक दर्दनाक अनुभव छोड़ जाता है। बलात्कार केवल एक महिला के प्रति अपराध नहीं है, यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है।

(24) हालाँकि, 25.06.2002 को हुई घटना के बाद, पीड़िता के पिता की 02.07.2002 को मृत्यु हो गई और पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को एक सप्ताह की छोटी सी अवधि में परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खोकर दूसरा झटका लगा। पीड़िता के पिता बी.डी.ओ. में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। कार्यालय, बरवाला और वह परिवार यानी पत्नी, तीन बेटियों और एक बेटे का भरण-पोषण कर रहा था। पीड़िता को करीबी रिश्तेदार द्वारा बलात्कार किए जाने की पीड़ा का सामना करने के अलावा, अपने पिता को भी खोना पड़ा, जिनकी 02.07.2002 को मृत्यु हो गई। (कृष्ण की पत्नी) के बयान के अनुसार, कृष्ण (शिकायतकर्ता के बहनोई) ने परवीन को किरण से

शादी करने के लिए कहा था, लेकिन वह सहमत नहीं थी और राम किशन द्वारा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया था। घटना के 4-5 दिन बाद रामकिशन उसके पास आया और दुखी होकर उसने यह भी कहा कि वह आत्महत्या कर लेगा, अगले दिन राम किशन ने वाटर वर्क टैंक, हिसार में कूदकर आत्महत्या कर ली।

(25) इस प्रकार, समाज में अस्वीकृति की भावना के साथ जीने के लिए कम आत्मसम्मान के अलावा, पीड़ित ने अपने पिता का भावनात्मक समर्थन खो दिया, जिनकी 28.06.2002 को शिकायत दर्ज होने के एक सप्ताह के भीतर यानी 02.07.2002 को मृत्यु हो गई।

(26) हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो सीआरएल में. 2014 की संख्या 24, 28.03.2014 को निर्णय लिया गया, एक पीड़िता को मुआवजा देते समय, जो राज्य द्वारा दिया जाना था, जिसके साथ आरोपियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था, पैराग्राफ 20, 21 और 23 में निम्नानुसार देखा गया है:-

"20) इस न्यायालय ने पी. रथिनम बनाम गुजरात राज्य, (1994) एससीसी (सीआरएल) 1163 में, जो पुलिस हिरासत में एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार से संबंधित था, ₹ 50,000/- का अंतरिम मुआवजा दिया। राज्य सरकार। इसी तरह, इस न्यायालय ने, रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास, (2000) 2 एससीसी 465 में, पीड़ित को मुआवजे के रूप में `10 लाख का भुगतान करने के उच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखा, जो एक बांग्लादेशी नागरिक था। इसके अलावा, इस न्यायालय ने एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5019/2012, जिसका शीर्षक सत्यपाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य है, में दिनांक 05.08.2013 के आदेश के तहत राज्य सरकार द्वारा दी गई अंतरिम राहत को `2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। दो पीड़ित लड़कियों को।

21) राज्य बनाम मोहम्मद मोइनुल हक और अन्य में बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय। (2001) 21 बीएलडी 465 में दिलचस्प बात यह है कि "बलात्कार की पीड़ितों को समाज में पुनर्वास के लिए बलात्कारियों की संपत्ति का आधा हिस्सा मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए।" यदि इस उदार तर्क को नहीं अपना रहे हैं तो कम से कम हमें पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की स्थिति में तो होना ही चाहिए।

23) मुख्य सचिव की रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे सहित उठाए गए कदमों को इंगित करती है। फिर भी, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि पीड़िता को पुनर्वास के लिए राज्य द्वारा कम से कम `5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तदनुसार, हम प्रतिवादी नंबर 1 (मुख्य सचिव के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य) को आज से एक महीने के भीतर `50,000

की पहले से स्वीकृत राशि के अलावा, `5 लाख का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा, पीड़िता की मां के नाम पर दिए जाने वाले लाभों के संबंध में भी हमें कुछ आपत्तियां हैं, जब पीड़िता खुद बालिग हो (यानी लगभग 20 वर्ष की आयु)। इस प्रकार, हमारे विचार में, यह उचित और लाभकारी होगा यदि पीड़िता को मुआवजा और अन्य लाभ सीधे दिए जाएं और तदनुसार हम ऐसा आदेश देते हैं।

(27) वर्तमान अपील गुण-दोष के आधार पर खारिज की जाती है। हालाँकि, उपरोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए, यह न्यायालय राज्य को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देता है और पीड़िता को 5 लाख रुपये भी दिए जाने चाहिए क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। 28.06.2002 को शिकायत दर्ज होने के बाद 02.07.2002।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा